भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5634

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर देने के लिए

बिहार में आकांक्षी जिले

5634. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपौल जिलो बिहार के विकसित जिलों में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चयन के लिए अन्य जिलों की तुलना में 'डाटा सेट' और 'वेटेज पॉइंट' के अनुसार सुपौल जिले की स्थिति क्या है;

(ग) सुपौल सहित बिहार के विभिन्न जिलों के 'डेटा सेट' और 'वेटेज पॉइंट' का ब्यौर क्या है;

(घ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों के तेजी से विकास के लिए चयन प्रक्रिया किन-किन वर्ष-वार तिथियों को पूरी की गई है;

(ङ) क्या उक्त चयन प्रक्रिया के तहत सुपौल पर भी विचार किया गया है;

(च) क्या सुपौल एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जिससे प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण इसकी विकास प्रक्रिया रुक जाती है; और

(छ) यदि हां, तो सुपौल जिले को उक्त कार्यक्रम में किस आधार पर शामिल नहीं किया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) वर्तमान में, नीति आयोग में किसी भी जिले को विकसित या अन्यथा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) जनवरी 2018 में, नीति आयोग ने एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उन जिलों की पहचान की, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई थी। इन जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में परिभाषित किया गया और इन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस पद्धति के अनुसार, बिहार में आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए आठ जिलों में 2018 में सुपौल जिले की तुलना में समग्र रूप से कम प्रगति हुई थी। इसके अलावा, बिहार में गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित जिलों के रूप में पहचाने गए 5 और जिलों को भी आकांक्षी जिला

की परिभाषा दी गई। इस सूची में सुपौल का नाम नहीं था। बिहार में 13 आकांक्षी जिलों की सूची **अनुलग्नक- II** में दी गई है।

(ग) से (घ) डाटा सेटों की सूची और इन जिलों के चयन के लिए उनसे संबंधित भारांक **अनुलग्नक-I** में हैं। वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। 2018 में उपलब्ध डेटा मूल्यों और संलग्न भारांक के आधार पर, डेटा को सामान्य करने के लिए एक मानकीकृत सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करके देश के सभी जिलों के सूचकांक मूल्य की गणना की गई थी। इसके बाद, उनके सूचकांक मूल्यों के आधार पर, जिलों की रैंकिंग की गई। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद द्वारा "सबसे अधिक प्रभावित" के रूप में वर्गीकृत 35 जिलों को भी शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य से कम से कम एक कम स्कोर वाले जिले को शामिल करने का प्रयास किया गया था। नीति आयोग ने शॉर्टलिस्ट किए गए जिलों की सूची को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया और अनुरोध किया कि यदि राज्य किसी भी बदलाव का सुझाव देता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। चयन प्रक्रिया को जनवरी 2018 तक अंतिम रूप दे दिया गया।

(ङ) जी हां । चूंकि जिले को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बिहार के सभी जिलों से संबंधित डेटा की जांच की गई थी, अत: ऊपर (ग) से (घ) में उल्लिखित जिलों की रैंकिंग करते समय सुपौल जिले पर विचार किया गया ।

(च) बाढ़ संभावित क्षेत्रों की जिलेवार सूची केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। हालांकि, देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का आकलन विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया गया है, और वर्ष 1953-2010 के दौरान किसी भी वर्ष में बाढ़ से प्रभावित अधिकतम क्षेत्र की सीमा 49.815 मिलियन हेक्टेयर, होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(छ) बिहार में शार्टलिस्ट किए गए जिलों ने 2018 तक सुपौल की तुलना में चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में या तो कम प्रगति दिखाई थी या वामपंथी उग्रवाद से अधिक प्रभावित हुए थे। इसलिए सुपौल का चयन नहीं किया गया।

*****

अनुलग्नक-I

<u>आकांक्षी जिलों के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट और भारांक की सूची</u>

डेटाबेस	**क्षेत्र**	**भारांक**
शारीरिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार (सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-वंचन 7)	वंचन (25 %)	25 %
प्रसव-पूर्व देखभाल [राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण(एनएचएफएस-4)]	स्वास्थ्य और पोषण (30%)	7.5 %
सांस्थानिक प्रसव (एनएचएफएस -4)		7.5 %
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अवरुद्ध विकास (एनएफएचएस-4)		7.5 %
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अपक्षय (एनएफएचएस-4)		7.5 %
प्रारंभिक ड्रॉपआउट दर [एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) 2015-16]	शिक्षा (15%)	7.5 %
असंतोषजनक विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (यू-डीआईएसई 2015-16)		7.5 %
बिजलीरहित परिवार (विद्युत मंत्रालय)	इन्फ्रा (30%)	7.5 %
पृथक शौचालयरहित परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)		7.5 %
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अछूते गांव (ग्रामीण विकास मंत्रालय)		7.5 %
जल सुविधारहित ग्रामीण परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)		7.5 %
कुल		**100%**

बिहार के 13 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र. सं .	**राज्य**	**जिला**
1.	बिहार	सीतामढ़ी
2.	बिहार	अररिया
3.	बिहार	पूर्णिया
4.	बिहार	कटिहार
5.	बिहार	मुजफ्फरपुर
6.	बिहार	बेगुसराय
7.	बिहार	खगड़िया
8.	बिहार	बांका
9.	बिहार	शेखपुरा
10.	बिहार	औरंगाबाद
11.	बिहार	गया
12.	बिहार	नवादा
13.	बिहार	जमुई

बारहवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंधन और क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों पर कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1953-2010 के दौरान किसी भी वर्ष में बाढ़ से प्रभावित अधिकतम क्षेत्र की सीमा

क्र. सं .	राज्य	अधिकतम प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)
1	आन्ध्र प्रदेश*	9.040
2	अरूणाचल प्रदेश	0.207
3	असम	3.820
4	बिहार	4.986
5	छत्तीसगढ़	0.089
6	दिल्ली	0.458
7	गोवा	0.000
8	गुजरात	2.050
9	हरियाणा	1.000
10	हिमाचल प्रदेश	2.870
11	जम्मू और कश्मीर	0.514
12	झारखंड	0.000
13	कर्नाटक	0.900
14	केरल	1.470
15	मध्य प्रदेश	0.377
16	महाराष्ट्र	0.391
17	मणिपुर	0.080
18	मेघालय	0.095
19	मिजोरम	0.541
20	नागालैंड	0.009
21	ओडिशा	1.400
22	पंजाब	2.790
23	राजस्थान	3.260
24	सिक्किम	1.170
25	तमिलनाडु	1.466
26	त्रिपुरा	0.330
27	उत्तर प्रदेश	7.340
28	उत्तराखंड	0.002
29	पश्चिम बंगाल	3.080
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.030
31	चंडीगढ़	-
32	दादरा और नगर हवेली	-
33	दमन और दीव	-
34	लक्षद्वीप	-
35	पुदुचेरी	0.050
	कुल	**49.815**

* पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की घोषणा से पहले)।